रजिस्ट्री सं० डी-.222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 30, 1966 (श्रावण 8, 1888)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 30, 1966 (SRAVANA 8, 1888)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 18 जुलाई 1966 तक प्रकाशित किये गये थे :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 18th July 1966 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
124	No. 104/ITC(PN)/66, dt. 12th July, 1966	Ministry of Commerce	Import of raw materials, components and spares by scheduled industries not borne on the books of DGTD and non-scheduled industries other than small scale units for the period April 1966-March 1967.
125	No. 7/66, dt. 13th July, 1966	-Do-	Import trade control—Open General Licence No. LXXXI.
126	No. 105-ITC(PN)/66, dt. 14th July, 1966	-Do-	Devaluation of rupee—consequential increase in the rupee value of import licences.
127	No. 106-ITC(PN)/66, dt. 18th July, 1966	-Do-	Liberalisation of policy for import of raw materials, components and spares by actual users in the small scale sector for the period April 1966-March 1967—Supply of photos—state copies of import licences.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ (Pages)
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों के संबंधित अधिसूचनाएं ..	535
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	677
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं ..	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं ..	431
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट ..	—

	पृष्ठ (Pages)
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1315
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii) (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2143
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश ..	187
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	501
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	281
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	109
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	489
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	155
पूरक सं० 31—	
23 जुलाई 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	1067
2 जुलाई 1966 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	1079

	Pages
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	535
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	677
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	431
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1315
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ...	2143
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	187
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	501
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	281
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	109
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	489
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	155
SUPPLEMENT No. 31—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 23th July 1966	1067
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 2nd July 1966	1079

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधेतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 14 जुलाई 1966

शुद्धिपत्र

स० 20/7/64-ए० आई० एस० (I)—दिनांक 26 फरवरी, 1966 को भारत के राजपत्र भाग I खंड I में प्रकाशित इस मंत्रालय की दिनांक 23 फरवरी 1966 की अधिसूचना स० 20/7/64-ए० आई० एस० (I) में निम्नांकित शुद्धियां कर दी जायें :—

क्रम सं०	निर्देश	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1.	पृष्ठ 163, स्तंभ 1, पैरा 1, अंतिम पंक्ति	जाना	जाता
2.	उसी पृष्ठ पर, स्तंभ 1, अंतिम पैरा, पहली पंक्ति . .	दिए ऐच्छिक विषयों	दिए गए ऐच्छिक विषयों
3.	पृष्ठ 164, स्तंभ 1, पैरा (v) का सब-पैरा 2, दूसरी पंक्ति	"प्राइम भूवर"	"प्राइम मूवर"
4.	उसी पृष्ठ पर, स्तंभ 1, विषयों की सूची में क्रम सं० (8)	अंग्रेज़ी साहित्य (1708-1935)	अंग्रेजी साहित्य (1798-1935)
5.	उसी पृष्ठ पर, स्तंभ 2, विषयों की सूची में क्रम स० (12) (ब)	जिसमें प्रयोगिक मनोविज्ञान	जिसमें प्रायोगिक मनोविज्ञान
6.	उसी पृष्ठ पर, स्तंभ 2, अनुसूचित भाग (क) में पैरा 2, पहली पंक्ति	प्रश्न इस प्रकार को होंगे	प्रश्न इस प्रकार के होंगे
7.	उसी में अंतिम पंक्ति	के लिये श्रेय जाएगा	के लिए श्रेय दिया जाएगा
8.	पृष्ठ 165, स्तंभ 1, भाग ख में पैरा 2 अंतिम पंक्ति	(रीजिड)	(रिजिड)
9.	उसी पृष्ठ पर स्तंभ 2, पैरा 2, पहली पंक्ति	विद्यदणु	विद्युदणु,
10.	उसी पृष्ठ पर स्तंभ 2 में . . .	5. **रसायन अकार्बनिक रसायन।**	'5. रसायन' को ऊपर **मुख्य** शीर्षक बनाना चाहिए
11.	उसी पृष्ठ पर स्तंभ 2 में उप-शीर्षक **कार्बनिक रसायन** में, दूसरी पंक्ति	संतुत्प	संतृप्त
12.	पृष्ठ 166, स्तंभ 1, पैरा सं० 8 . . .	8. **भूविज्ञान** को मुख्य शीर्षक	बनाना चाहिये ।
13.	उसी में, पहली पंक्ति	भौतिक, भविज्ञान	भौतिक भूविज्ञान
14.	उसी पृष्ठ पर स्तभ 2, 9. **भूगोल** मे, चौथी पंक्ति . .	विष्चन	विश्चन
15.	पृष्ठ 167, स्तभ 2, 23 (क) में . . .	स्वामित्व लेखे	स्वाभिस्व लेखे
16.	पृष्ठ 168, स्तंभ 1, 24. के पैरा 1 मे तीसरी पंक्ति .	क्षेव और काईकारी	क्षेम और काईकारी
17.	पृष्ठ 168, स्तंभ 2, उप-शीर्षक **सामान्य** मे आठवी पंक्ति .	पद्धतिबल	प्रतिबल
18.	पृष्ठ 169, स्तंभ 1, उप-शीर्षक **वायु संपीडक** मे अंतिम सब-पैरा	आह हैड	क्रास हैड
19.	पृष्ठ 169, स्तंभ 1, भाग ग में 1 (क) का दूसरा सब-पैरा .	**विश्लेषण वातस्विफ्-चर के फलन**	**विश्लेषण** एक अलग शीर्षक होना चाहिये
20.	उसी में चौथी पंक्ति में	गौर निम्निष्ठ	और निम्निष्ठ
21.	उसी पृष्ठ पर, स्तभ 2, दूसरा विषय . . .	2. **उच्च भौतिकी द्रव्य** . .	2. **उच्च भौतिकी** को ऊपर शीर्षक के रूप में लिखना चाहिए।
22.	उसी में, उप-शीर्षक आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत , दूसरी पंक्ति	द्वैत प्रकृति	द्वैत प्रकृति
23.	उसी पृष्ठ एवं स्तंभ में, शीर्षक 3. **उच्च रसायन** में, पांचवी पंक्ति	BE,.....HF, Z_1	Be,.....HF ZV
24.	पृष्ठ 170, स्तंभ ऊपर से पैरा 2, पहली पक्ति . .	यौगियों	यौगिकों
25.	पृष्ठ 170, स्तंभ 2, शीर्षक 6 के नीचे दूसरा सब-पैरा .	संयचना तथा क्षेत्र भू-विज्ञानपटल विरूपण	संरचना तथा क्षेत्र भू-विज्ञान-पटलविरूपण ।
26.	उसी में तीसरा सब-पैरा, चौथी पंक्ति . . .	विभिन्न कालों पृथ्वी	विभिन्न कालों में पृथ्वी

क्रम सं०	निर्देश	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
27.	उसी में छठा सब-पैरा, छठी पंक्ति	भूरसायनिक पुर्वेक्षण	भूरासायनिक पूर्वेक्षण
28.	उसी में सातवीं पंक्ति	अमस्क-प्रसाधन	अयस्क-प्रसाधन
29.	उसी पृष्ठ पर नीचे शीर्षक सं० 8 में . . .	लैम्प	लैम्ब
30.	पृष्ठ 171, स्तंभ शीर्षक 9 (क) में मगध का पतन उप-शीर्षक में	चोल, चर	चोल, चेर
31.	उसी में, शीर्षक 9(ख) में	(मुगल साम्राज्य (1526-1807)	मुगल साम्राज्य (1526-1707)
32.	उसी में तीसरी पंक्ति	राज्य यान्तराल	राज्यान्तराल
33.	उसी में, स्तंभ 2, ऊपर से दूसरी पंक्ति . . .	ब्रम्हा	ब्रह्मा
34.	पृष्ठ 171, स्तंभ 2, सबसे अंतिम पंक्ति . . .	नाज्जिम्	नाज्जिम
35.	पृष्ठ 172 स्तंभ 2, सबसे नीचे से दूसरी पंक्ति . .	तथा प्राक्रिया	तथा प्रक्रिया
36.	पृष्ठ 173, स्तंभ 1, दूसरा पैरा, पांचवी पंक्ति . .	अद्देश्य	उद्देश्य
37.	पृष्ठ 174, स्तंभ 1, पहली पंक्ति	अभिकरन	अभिकरण

ओ० स० मारवा, अवर सचिव

नई दिल्ली-11, दिनांक 30 जुलाई 1966

सं० 6/5/66-सी० एस०(1)—निम्नलिखित सेवाओ/पदों में खाली जगहों को भरने के लिए फरवरी, 1967 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगियता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं:—

(i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा-सहायक ग्रेड,

(ii) भारतीय विदेश सेवा (बी०) सामान्य संवर्ग (सहायक) का ग्रेड iv,

(iii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा-ग्रेड iv (सहायक); और

(iv) केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय विदेश सेवा (बी०)/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में, सम्मिलित न होने वाले कुछ विभागों/केन्द्रीय सरकार के कुछ दफ्तरों में विद्यमान सहायकों के पद।

एक उम्मीदवार उपर्युक्त किसी भी एक या अधिक सेवाकों/पदों के लिए प्रतियोगी हो सकता है। वह जितनी सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगी रहना चाहता है उनका उल्लेख अपने आवेदन-पत्र में कर दे। उम्मीदवारों को सावधान किया जाता है कि उनकी किसी ऐसी सेवा में/पद पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायगा जिसका कि उन्होंने उल्लेख न किया हो।

नोट—उम्मीदवारो से अपेक्षा की जाती है कि जिन सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगी होना चाहते हों उनका अधिमान-क्रम से स्पष्ट उल्लेख करें। उम्मीदवार जिन सेवाओ/पदों के लिए प्रतियोगी हो उनके अधिमान-क्रम में परिवर्तन के लिए कोई भी आवेदन तब तक विचारणीय न होगा, जब तक कि परिणाम घोषित होने के पंद्रह दिन के भीतर, इस आशय का आवेदन लोक संघ सेवा आयोग या गृह मंत्रालय में पहुंच न गया हो।

2. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमो के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

3. उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) कोई भारत-मूलक व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका, और पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उगांडा, तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तंगानिका तथा जंजीबार) देशो मे प्रव्रजन (माइग्रेट) किया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियो के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाणपत्र होना चाहिए और यदि वह (च) कोटि का हो तो पात्रता प्रमाणपत्र एक साल के लिए दिया जायगा जिसके बाद उम्मीदवार की नौकरी तभी जारी रखी जाएगी जब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

लेकिन नीचे लिखे प्रकार के उम्मीदवारों से पात्रता प्रमाणपत्र लेना आवश्यक नही होगा—

(i) वे व्यक्ति जिन्होंने 19 जुलाई 1948, से पहले पाकिस्तान से भारत मे प्रव्रजन (माइग्रेट) किया हो और जो तब से आम तौर पर भारत मे ही रह रहे है।

(ii) वे व्यक्ति जिन्होने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत मे प्रव्रजन (माईग्रेट) किया हो और संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप मे रजिस्टर करा लिया हो।

(iii) ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक, जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी 1950, से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार नौकरी कर रहे है और जिनके सेवाकाल मे कोई भंग (ब्रेक) नहीं हुआ है।

लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल में भंग हुआ हो और उसने 26 जनवरी, 1950, के बाद उक्त सेवा दुबारा शुरू की हो या शुरू कर सके तो उसे भी औरों की तरह पात्रता प्रमाणपत्र देना होगा ।

एक और शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) कोटि के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग (सहायक) के ग्रेड IV में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र दिए जाने की शर्त के साथ अनन्तिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है ।

4. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो या पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का निवासी न हो या भारत के भूतपूर्व पुर्तगाली राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव का निवासी न हो या पुर्वी अफ्रीका के कैनिया, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ टान्जानिया (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) का प्रव्रजक न हो उसे इस परीक्षा में अधिक-से-अधिक दो बार बैठने दिया जाएगा । यह प्रतिबन्ध सन् 1962 की परीक्षा के समय से लागू है ।

नोट 1—यदि उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिए यह मान लिया जाएगा कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में एक बार उक्त परीक्षा के अंतर्गत आनेवाली सब सेवाओं/पदों के लिए बैठ चुका है ।

नोट 2—यदि उम्मीदवार ने वस्तुतः एक या अधिक विषयों की परीक्षा दी हो तो यह माना जाएगा कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ चुका है ।

5 (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुकी हो । किन्तु पहली जनवरी 1967 को किसी भी हालत में उसकी आयु पूरे 24 साल की न हो, अर्थात्, उसका जन्म 2 जनवरी 1943 से पहले और पहली जनवरी 1947 के बाद न हुआ हो ।

किन्तु 2 जनवरी, 1943 से पहले पैदा हुए ऐसे उम्मीदवार इस परीक्षा में विशेष मामले के तौर पर सम्मिलित हो सकेंगे जो कि 2 अगस्त 1942 से पूर्व न पैदा हुए हों । यह छूट केवल 1967 में होनें वाली परीक्षा के लिए ही उपलब्ध होगी ।

(ख) ऊपर बतायी गयी ऊपरी आयु-सीमा में इस प्रकार छूट दी जा सकती है:—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम-जाति का हो तो अधिक-से-अधिक पांच वर्ष तक;

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्व पाकिस्तान का वास्विक विस्थापित व्यक्ति हो तो 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित आदिम-जाति का हो तो तथा पूर्व पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष तक;

(iv) यदि उम्मीदवार पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो और उसने किसी समय फ्रांसीसी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक-से-अधिक पाच वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (रिपैट्रियेट) हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक आठ वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार भारत में मूलक व्यक्ति हो और उसने पूर्वी अफ्रीका के देशों केनिया, युगान्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आंफ तान्जानिया (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक ;

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (रिपैट्रिएट) हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन को या उसके बाद भारत से प्रव्रजन किया हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक ;

(ix) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी आदिम अनुसूचित जाति का हो और बर्मा से वास्तविक भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ;

(x) रक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों के मामले में अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक;

(xi) रक्षा सेवाओं के ऐसे विकलांग कर्मचारियों के लिये जो कि अनुसूचित जाति या आदिम अनुसूचित जाति के हों तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक **1 ऊपर बताई गई स्थितियों को छोड़कर और किसी भी हालत में ऊपर निर्धारित आयु-सीमाओं में छूट नहीं दी जा सकती है ।**

6. उम्मीदवार के पास परिशिष्ट 1 में उल्लिखित किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिये, या उसमें परिशिष्ट-1-क में उल्लिखित योग्यताओं में से कोई योग्यता होनी चाहिए ।

नोट 1—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसमें पास होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन जिसके परिणाम की सूचना उसे अभी तक नहीं मिली हो, तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन-पत्र भेज सकता है । जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन-पत्र दे सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाए । ऐसा उम्मीदवार यदि अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हो तो उसे परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम (प्रोविजनल) मानी जाएगी; और यदि वह उक्त परीक्षा को पास करने का प्रमाण जल्दी-से-जल्दी, और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक-से-अधिक दो महीने के अन्दर, प्रस्तुत नहीं करता तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकती है ।

नोट 2—विशेष मामलो में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार को, जिसमें उक्त योग्यता न हो, शैक्षिक दृष्टि से योग्यता मान सकता है, बशर्ते कि उसने अन्य संस्थाओं में से किसी के द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है ।

नोट 3—जो उम्मीदवार अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों, पर जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हों जिन्हें परिशिष्ट 1 में शामिल नहीं किया गया हो, वे भी आयोग को अपना आवेदन-पत्र भेज सकते हैं, और आयोग चाहे तो उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है ।

7(क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी

स्थिति में विवाह करता है कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि में किये जाने के कारण अमान्य (वायड) हो जाता है, उसे उन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति का जिनके लिए इस प्रतियोगिता-परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जानी हैं तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है और वह उस पुरुष उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

(ख) जिस महिला उम्मीदवार का विवाह इस कारण अमान्य (वायड) हो जाए कि उक्त विवाह के समय उसके पति की एक जीवित पत्नी पहले से है या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी उक्त विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो, वह उन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति की, जिनके लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, तब तक पात्र नहीं मानी जाएगी जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है और वह उस महिला उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

(ग) विवाहित महिला उम्मीदवार आम तौर पर भारतीय विदेश सेवा (बी) के सामान्य संवर्ग (सहायक) के ग्रेड IV में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। इस ग्रेड की अविवाहित महिला को अपना विवाह करने से पहले सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी। विवाह होने के बाद किसी भी समय यदि सरकार को यह संतोष हो जाए कि उसकी पारिवारिक और घरेलू जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि उनके कारण सेवा के एक सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्यों को उचित रूप से और दक्षता-पूर्वक पूरा करने में बाधा पड़ सकती है तो उसे सेवा से त्यागपत्र देने के लिए कहा जा सकता है।

8. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत में पहले से ही सरकारी सेवा कर रहा हो, उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले विभाग-अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह सम्बन्धित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को दक्षतापूर्वक न निभा सके। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति पर विचार किए जाने की संभावना हो।

10 परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एडमीशन) न हो।

13. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के अनुबंध-I में निर्धारित फीस देनी होगी।

14. आवेदन-पत्र में मांगी गई सिफारिशों को छोड़कर किसी और सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार किसी और प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

15 यदि कोई उम्मीदवार इस बात का दोषी हो या आयोग द्वारा इस बात का दोषी ठहराया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण-पत्र आदि पेश किए हैं या ऐसे प्रमाण-पत्र पेश किए हैं जिनमें कोई छेड़ की गई है या कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत है या झूठी है या कोई तथ्य छिपाया है या परीक्षा में बैठने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा-भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा-भवन में अनुचित आचरण किया है तो उसका दांडिक अभियोजन (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) किया जा सकता है —

(क) साथ ही, उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए —

(i) आयोग उम्मीदवारों के चुनाव के लिए ली जाने वाली किसी भी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से रोक सकता है, और

(ii) केन्द्रीय सरकार, सरकारी नौकरी करने से रोक सकती है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो, तो उपयुक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

16 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए उतनी खाली जगहें आरक्षित की जाएंगी जितनी कि सरकार तय करे।

अनुसूचित जाति/आदिमजाति का अर्थ है ऐसी कोई भी जाति/आदिमजाति जो कि अनुसूचित जाति/आदिमजाति सूची (तरमीम) आदेश, 1956 में उल्लिखित हो और जिसके साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिमजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956; संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956; संविधान (अंदमान तथा निकोबार द्वीप) अनुसूचित आदेश-जाति आदेश, 1959; संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962; संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम-जाति आदेश, 1962 और संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1961 पढ़े जायें।

17 परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांक के आधार पर उनके योग्यता-क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवार योग्यता-क्रम के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा में योग्य माने गए हों।

लेकिन शर्त यह है कि यदि आयोग अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा/पद के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मान के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, प्रशासन की कुशलता को ध्यान में रखते हुए उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दे तो उस सेवा/पद में, अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिमजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित खाली जगहों पर उसकी नियुक्ति की सिफारिश की जाएगी।

नोट 1—आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवार द्वारा बताई गई पसंदों के क्रम पर उचित ध्यान दिया जाएगा (**देखिए**—आवेदन-पत्र का खाना 27) लेकिन उम्मीदवार को ऐसी किसी भी सेवा में ऐसे किसी भी पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसके लिए उसकी परीक्षा ली गई हो।

नोट 2—हर एक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा ।

18. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि पर की जाएंगी । यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जा सकेगी ।

19. उम्मीदवारों को सहायक-ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर कम-से-कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आयोग द्वारा ली जाने वाली टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी । यदि वे नियत अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें तो वे सहायक-ग्रेड में आगे वेतन-वृद्धि पाने के तब तक अधिकारी न होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाए और परीक्षा पास कर लेने पर या उससे छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मानकर फिर से इस प्रकार नियत किया जाएगा, कि उनकी वेतन-वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी । परन्तु, जितनी अवधि के लिए वेतन-वृद्धि रोकी गई थी उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जाएगा ।

20. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ब्री०) में सहायकों और भारत के चुनाव आयोग तथा पर्यटन विभाग में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट-III में संक्षेप में दी गई हैं ।

के० त्यागराजन, अवर सचिव

परिशिष्ट-I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची
(देखिये नियम 6)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान-मण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम से स्थापित किए गए हों, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (1956) की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के रूप में मान्य घोषित संस्थाएं ।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय और मांडले विश्वविद्यालय ।

इंग्लैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, केम्ब्रिज, डर्हम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मैन्चेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शेफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय ।

स्काटलैंड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लास्को और सैंट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय ।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज), नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन, दि क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट ।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय, सिंध विश्वविद्यालय, और राजशाही विश्वविद्यालय ।

परिशिष्ट I-क

परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये मान्यता-प्राप्त योग्यताएं

1. गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी का "अलंकार"
2. काशी विद्यापीठ बनारस का "शास्त्री"
3. फ्रांसीसी परीक्षा "बकालारे" (Baccalawreat)
4. फ्रांसीसी परीक्षा "प्रापेदनीक" (Propedentique)
5. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् से ग्राम-सेवाओं में डिप्लोमा ।
6. विश्वभारती विश्वभारती विश्वविद्यालय का ग्राम-सेवा डिप्लोमा ।
7. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से वाणिज्य में डिप्लोमा ।
8. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सिविल, यांत्रिक या बिजली इंजीनियरी में डिप्लोमा ।
9. भारतीय खान और अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान विद्यालय, धनबाद, से खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा ।
10. श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पाण्डिचेरी, का "उच्च पाठ्यक्रम" यदि पूर्ण छात्र (फुल स्टूडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

परिशिष्ट-II

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे:—

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1. निबन्ध . .	100	2 घंटे
2. सामान्य अंग्रेजी . .	200	3 घंटे
3. अंकगणित . .	100	2 घंटे
4. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है .	100	2 घंटे

2. **परीक्षा का विषय**—विवरण साथ लगी अनुसूची में दिया गया है ।

3. उम्मीदवार प्रश्नपत्र 1 और प्रश्नपत्र 4 का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकते हैं । प्रश्नपत्र 2 और प्रश्नपत्र 3 का उत्तर भी सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में ही देना होगा ।

नोट 1—यह विकल्प पूरे प्रश्नपत्र के लिए होगा, न कि उसी प्रश्नपत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिए ।

नोट 2—उक्त प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प चाहने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन-पत्र के खाना 7 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए; नहीं तो, यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे ।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है ।

6. उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में दिए गए अंकों में से आयोग द्वारा निर्धारित अंक इसलिए काट लिए जाएंगे कि कहीं कोरे सतही ज्ञान का उसे लाभ न मिल जाए ।

7. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के पूर्णांक में से 5 प्रतिशत काट लिए जाएंगे ।

8. परीक्षा के सभी विषयों में कम-से-कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा ।

9. उम्मीदवारों से मुद्रा, तौल और माप की मेट्रिक प्रणाली से परिचित होने की आशा की जाती है । प्रश्नपत्रों में यथावश्यक मुद्रा, तौल और माप की मेट्रिक प्रणाली से सम्बंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

अनुसूची

परीक्षा का विषय-विवरण

1. **निबन्ध :** दिए गए कुछ विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा ।

2. **सामान्य अंग्रेजी :**

(i) **सार-लेखन और मसौदा-लेखन :** अंग्रेजी समझाने और लिखने की शक्ति की परीक्षा करने के लिये प्रश्न पूछे जायेंगे । आम तौर पर, संक्षेप या सार लिखने के लिये अंश (पेसेजेज़) दिये जायेंगे । उम्मीदवारों को कुछ सामग्री दी जाएगी और उन्हें उस सामग्री का समुचित उपयोग करते हुए पत्रों, शापनों आदि के मसौदे तैयार करने को भी कहा जाएगा ।

(ii) पर्यायों, विलोमों, शब्दों तथा वाक्यांशों के मुहावरेदार प्रयोग और सामान्य त्रुटियों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे ।

(iii) शब्द भेद (पार्टस ऑफ स्पीच), वाक्य विश्लेषण, वाक्यरचना तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन (डायरेक्ट एंड इन्डायरेक्ट स्पीच) ।

नोट—प्रश्नपत्र 2 में सार-लेखन के लिये 75 अंक, मसौदा-लेखन के लिये 75 अंक और व्याकरण, मुहावरों आदि के लिये 50 अंक होंगे ।

प्रश्नपत्र 1 और 2 का उद्देश्य उम्मीदवारों की शुद्ध भाषा लिखने की योग्यता की परीक्षा करना है । वाक्य-विन्यास, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग पर ध्यान दिया जाएगा ।

3. अंकगणित :

अनुपात तथा समानुपात, प्रतिशतता, औसत, आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण, रेखिक ग्राफों को पढ़ना और आंकड़ों का सारणीकरण ।

प्रश्नों का उद्देश्य यह मालूम करना है कि उम्मीदवार कार्य को शीघ्रता से, ठीक-ठीक और समझ बूझ के साथ कर सकते है या नहीं ।

4. सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है :

सामयिक घटनाओं का ज्ञान और जो कुछ हम प्रतिदिन देखते और अनुभव करते है उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान, जो एक ऐसे साधारण पढ़े-लिखे आदमी को होना चाहिये जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो । इस प्रश्न-पत्र में भारतीय भूगोल सम्बन्धी प्रश्न भी पूछे जायेंगे । इस प्रश्नपत्र में भारतीय इतिहास सम्बन्धी ऐसे प्रश्न भी पूछे जायेंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकता है ।

परिशिष्ट-III

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिये इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है

1. (i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड है :—

(1) सेलेक्शन ग्रेड (उप-सचिव या समकक्ष)—रु० 1100–50–1300–60–1600–100–1800

(2) ग्रेड (अवर सचिव या समकक्ष)—रु० 900–50–1250

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 350–25–500–30–590-कु० रो०–30–800–कु० रो०–30–830–35–900

(4) सहायक ग्रेड—रु० 210–10–270–15–300–कु० रो०–15–450–कु० रो०–20–530

नोट—जो सहायक अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किये जाते है, उन्हें कम-से-कम 400 रु० प्रति मास वेतन दिया जाएगा ।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । परिवीक्षा की इस अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा ।

(3) परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है ।

(4) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किये गये सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जाएगा । परन्तु, उनका किसी भी समय ऐसे किसी भी अन्य मंत्रालय या कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

(5) सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(6) जिन व्यक्तियों को उनके विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो, वे अपनी नियुक्ति के बाद भारतीय विदेश सेवा (बी) या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना के संवर्ग (कैडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे ।

1. (ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा

(क) जहां तक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का सम्बन्ध है, रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी की सेवा की शर्तें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना द्वारा नियमित होती हैं, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के समान ही है ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नीचे लिखे ग्रेड शामिल है :—

(i) सहायक निदेशक अवर सचिव—रु० 900–50–1250

(ii) अनुभाग अधिकारी—रु० 350–25–500–30–590 कु० रो०–30–800–कु० रो०–30–830–35–900

(iii) सहायक—रु० 210–10–270–15–300–कु०रो०–15–450–कु० रो० 20–530

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है । जो सहायक, अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किये जाते है, उन्हें कम-से-कम 400 रु० प्रतिमास वेतन दिया जाता है ।

(ग) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । परिवीक्षा की इस अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा ।

(घ) परिवीक्षा-अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा-अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है ।

(ङ) सहायक इस सबन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(च) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारी अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते जैसे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारी किए जा सकते हैं।

(छ) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी, (परिवीक्षाधीन अधिकारी भी)—

(i) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और

(ii) जिस दिन कार्य सम्भाल उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले गैर-अंशदायी रेल भविष्य निधि के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ज) रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को अन्य रेल कर्मचारियों के समान ही पास और सुविधा-टिकट-आदेश की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(झ) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान समझा जाएगा; परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में वे उन नियमों से शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में है।

1. (iii) **भारतीय विदेश सेवा (बी०)**

विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय राजनयिक कांसुली तथा व्यापार मिशनों और केंद्रों (पोस्ट्स) में सहायकों के सभी पद तथा वाणिज्य मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड में शामिल किए गए हैं। भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग में विभिन्न ग्रेड इस प्रकार है, इनमें ग्रेड-IV से नीचे के ग्रेड शामिल नहीं है:—

ग्रेड	पद	वेतनमान
ग्रेड-I	मुख्यालय में अवर सचिव विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों (पोस्ट्स) में प्रथम और द्वितीय सचिव	रु० 900-50-1250
एकीकृत ग्रेड-I और ग्रेड-III	मुख्यालय में सहचारी (अताशे) और अनुभाग अधिकारी, विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों में कांसुल और रजिस्ट्रार	रु० 350-25-500-30-590—कु० रो०—30-800—कु० रो० -30-830-35-900।
ग्रेड-IV	मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों केन्द्रों (पोस्ट्स) में सहायक	रु० 210-10-270-15-300—कु० रो०-15-450—कु० रो०-20-530।

नोट 1—एकीकृत ग्रेड-II और III तथा ग्रेड-IV में सीधे भर्ती की जाती है। एकीकृत ग्रेड-II और III में पदोन्नत सहायकों को न्यूनतम वेतन 400 रु० प्रतिमास दिया जाता है।

नोट 2—समय-समय पर लागू किए जाने वाले नियमों और आदेशों के अनुरूप ग्रेड के अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा के ज्येष्ठमान में पदोन्नत किया जा सकता है, जिसका वेतनमान रु० 900-50-1000-60-1600-50-1800 है।

2. भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग (सहायक) के ग्रेड-IV के लिये चुने गए उम्मीदवार स्थायी और दीर्घकालीन अस्थायी खाली जगहों पर नियुक्त किए जाएंगे। ये नियुक्तियां, सामान्यतया, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित उम्मीदवारों के योग्यताक्रम के अनुसार की जाएंगी; परन्तु जो उम्मीदवार विदेश सेवा के लिए योग्य नहीं होंगे, उनका नाम योग्यताक्रम में से निकाल दिया जाएगा। विदेश सेवा के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए उम्मीदवारों को एक चुनाव बोर्ड के सामने उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है, जिसका गठन विदेश मंत्रालय, नई-दिल्ली द्वारा किया जाएगा।

3. भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड-IV में सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखे जाएंगे। परिवीक्षा की इस अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा-मुक्त किया जा सकता है।

4. भारतीय विदेश सेवा (बी०) में नियुक्त व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्तियों से भारत में या भारत के बाहर कहीं भी सेवाएं ली जा सकती हैं।

5. भारत में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सदस्यों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते भी मिलेंगे जो उनके समकक्ष पदों वाले केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को मिलते हैं। विदेश में सेवा करते समय इन अधिकारियों को समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मानों के अनुसार विदेश भत्ता, सुफ्त सुसज्जित निवास, बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता, सज्जा भत्ता (आउटफिट अलाउंस) और अपने लिए और अपने परिवारों के लिए यात्रा-भाड़ा आदि की विशेष सुविधाएं मिल सकेंगी। ये सुविधाएं सरकार के सामान्य निर्णयों के अनुसार खत्म की जा सकती हैं या घटाई-बढ़ाई जा सकती हैं।

6. भारतीय विदेश सेवा (बी०) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा बी०) (भर्ती, संवर्ग, ज्येष्ठता और पदोन्नति) नियमावली, 1964, द्वारा तथा उन अन्य नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे, जिन्हें सरकार इसके बाद बनाए और इस सेवा पर लागू करे।

भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य संवर्ग (सहायक) के ग्रेड-IV में नियुक्त व्यक्ति भारतीय विदेश सेवा (शाखा बी०) (भर्ती, संवर्ग, ज्येष्ठता, और पदोन्नति) नियमावली, 1964 में दिए हुए उपबन्धों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

2. **चुनाव आयोग, भारत**

चुनाव आयोग में सहायकों के पद का वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के पदों के समान ही रु० 210-10-270-15-300-कु० रो०-15-450-कु० रो०-20-530 है। फिर भी, ये पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल नहीं है और इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होता।

2. सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा-अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परिक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवामुक्त किया जा सकेगा।

परिवीक्षा-अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा-अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है ।

सहायक इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे । इसके आगे दो और ऊंचे ग्रेड ये है :—

1—अनुभाग अधिकारी ग्रेड—रु० 350-25-500-30-590—कु० रो०-30-800—कु० रो०-30-830-35-900

2—अवर सचिव ग्रेड—रु० 900-50-1250 ।

3. **पर्यटन विभाग**

पर्यटन विभाग में सहायकों के पदों का वेतनमान रु० 210-10-270-15-300-द० रा०—15-450-द० रा०—20-530 है जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-IV के लिए निर्धारित है । किन्तु, ये पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में सम्मिलित नहीं है और इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पदों पर नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकते ।

सहायक के रूप में सीधे भरती किये गये व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन होंगे, और इस अवधि में उन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी । परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिये प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति दिखाने में या परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने का परिणाम सेवा से विमुक्ति हो सकता है ।

परिवीक्षा की समाप्ति पर सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति की, उसकी नियुक्ति पर पुष्टि कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक हो रहा तो उसे सेवा से विमुक्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा-अवधि आगे और उस सीमा तक बढ़ायी जा सकती है जितनी कि सरकार आवश्यक समझे ।

समय-समय पर एतविषयक नियमों के अधीन, सहायक लोग, सहायक निदेशक (प्रशासन) के उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे जिसका वेतनमान 400-25-500-30-590- द० रो०-30-800 रु० है ।

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 1966

सं० 12/1/66-ई० प्रा०—भारत रक्षा (सप्तम संशोधन) नियम, 1965 के नियम 135 बी० के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई केन्द्रीय सरकार निम्न अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रवासी सम्पत्ति के सहायक परिरक्षक भी नियुक्त करती है:—

(1) श्री खुशीराम, तहसीलदार, अनूपगढ तहसील, जिला गंगानगर, राजस्थान ।

(2) श्री सूरज कर्ण, तहसीलदार, तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर, राजस्थान ।

(3) श्री मथुरादास बिस्सा, तहसीलदार, तहसील कोलायट, जिला बीकानेर, राजस्थान ।

(4) श्री चतुर बिहारीलाल गुप्त, आर० ए० एस०, अतिरिक्त कलक्टर, बाड़मेर और जैसलमेर तहसील तथा जिले, राजस्थान ।

एस० बैनर्जी, उप-सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 1961

सं० एफ० 16-6/65-पी०ई० 4—शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ 16/6/65-पी०ई० 4, दिनांक 2 जून, 1966 के क्रम में—

महामान्या ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिन्धिया,
जय विलास महल,
ग्वालियर (म० प्रदेश)
को

इसी समय से तथा 16 अगस्त 1968 तक 'शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में केन्द्रीय संस्थानों के प्रशासन के लिये सोसायटी' के गवर्नर्स बोर्ड की एक सदस्या के रूप में नामजद किया जाता है ।

रोशन लाल आनन्द, अवर सचिव

परिवहन तथा विमानन मंत्रालय

परिवहन, नौवहन तथा पर्यटन विभाग

(परिवहन पक्ष)

संस्ताव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 1966

सं० -55-एम० ए० (9)/65—केन्द्रीय सरकार ने परिवहन तथा विमानन मंत्रालय, परिवहन, नौवहन तथा पर्यटन विभाग संस्ताव सं० 55-एम० ए० (9)/65 दिनांक 25 मई, 1966 में, जो भारत के राजपत्र के भाग I खंड 1 में प्रकाशित हुआ था, निम्न संशोधन किये है, अर्थात्:—

(1) मद 7 के विपरीत 'क—डेक यात्री कल्याणकारी समिति, बम्बई' शीर्षक के अन्तर्गत "मुख्य पत्तन अधिकारी तथा इंजीनियर, महाराष्ट्र की राज्य सरकार, बम्बई" **शब्दों के स्थान पर** "महाराष्ट्र सरकार के मुख्य पत्तन अधिकारी और उप-सचिव, भवन और संचार विभाग, बम्बई" **पढ़िए** ।

(2) मद 4 के विपरीत : "ग-डेक यात्री कल्याणकारी समिति, मद्रास" शीर्षक के अन्तर्गत "प्रवर यातायात प्रबन्धक (चालन), मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास" **शब्दों के स्थान पर** "उप-यातायात प्रबन्धक, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास" **पढ़िए** और मद 11 के विपरीत "श्री पी० मारुथि पिल्लई" **के स्थान पर** "श्री पी० मारुथाई पिल्लई" **पढ़िए** ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संस्ताव की एक प्रति, राष्ट्रपति के निजी व सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, (5 प्रतियां कमीटी ब्रांच सहित 10 प्रतियां) योजना आयोग, भारत सरकार के समस्त मंत्रालय, समस्त राज्य सरकार, अध्यक्ष, कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर, कलकत्ता, अध्यक्ष, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट, बम्बई, अध्यक्ष, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास, इंडियन नेशनल स्टीमशिप ओनर एसोसिएशन, सिंधिया हाउस, बनार्ड स्टेट, फोर्ट बम्बई, महानिदेशक नौवहन, कामर्स हाउस, बनार्ड स्टेट, फोर्ट बम्बई (100 अतिरिक्त प्रतियां जो भारत में नौवहन कंपनियों को वितरित की जायेंगी), नेशनल हारबर बोर्ड और नेशनल शिपिंग बोर्ड के सदस्य, डेक यात्री कल्याणकारी समिति, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रेषित कर दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संस्ताव सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

नागेन्द्र सिंह, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RULES

New Delhi-11, *the* 30*th July* 1966

No. F. 6/5/66-*CS*(*I*).—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in February, 1967 for the purpose of filling vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Central Secretariat Service—Assistants' Grade;

(ii) Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the Indian Foreign Service (B);

(iii) Railway Board Secretariat Service—Grade IV (Assistants);

(iv) Posts of Assistants in certain Departments/Offices of the Central Government not included within the purview of the Central Secretariat Service/Indian Foreign Service (B)/Railway Board Secretariat Service.

A candidate may compete in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to compete for. Candidates are warned that they will not be considered for appointment to any Service/post not specified by them.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to compete. No request for alteration in the preferences indicated by a candidate in respect of Services/posts for which he is competing would be considered, unless the request for such alteration is received in the Office of the Union Public Service Commission or the Ministry of Home Affairs within 15 days of the date of announcement of the result of the examination.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government of India and if he belongs to category (f) the certificate of eligibility will be issued for a period of one year after which such a candidate will be retained in service subject to his having acquired Indian citizenship.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution.

(iii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution *viz.*, 26th January 1950, and who have continued in such service since then without a break. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way :

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the Indian Foreign Service (B).

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

4. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination. This restriction is effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 2.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 24 years on the 1st Year, 1967 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January, 1943 and not later than 1st January, 1947.

Provided that a candidate who was born earlier than 2nd January, 1943 but not earlier than 2nd August 1942 shall also be eligible for admission to this examination as a special case. This relaxation would be admissible for the examination to be held in 1967 only.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of the disabled Defence Services personnel; and

(xi) up to a maximum of eight years in the case of the disabled Defence Services personnel who belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate must hold a degree of any of the universities enumerated in Appendix I, or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A Candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such a candidate will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if he does not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has has not the above qualification as educationally qualified provided that he has passed an examination, conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—Candidates who are otherwise eligible but who have taken degrees from foreign universities which are not included in Appendix I may also apply and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. (a) No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the Services/posts, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any male candidate from the operation of this rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the Services/posts, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.

(c) Women candidates who are married will not ordinarily be eligible for appointment to Grade IV of the General Cadre of the I.F.S. (B). A woman member of this Grade who is not married shall obtain the permission of the Government, in writing, before her marriage is solemnised. At any time, after the marriage a woman member of the Service may be required to resign from the service, if the Government is satisfied that her family and domestic commitments are likely to come in the way of the due and efficient discharge of her duties as a member of the Service.

8. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or temporary capacity must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the examination.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

10. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules if he is already in service under Government.

16. Reservations shall be made for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 and the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission in their discretion to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination :

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service/post, is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in that Service/post.

NOTE 1.—*Due consideration will be given to the preferences* expressed by a candidate at the time of his application (c.f. Col. 27 of the application form) but a candidate may be assigned to any Service/post for which the examination is held.

NOTE 2.—The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

18. Appointments will be made on probation for a period of two years. *The period of probation may be extended, if* considered necessary.

19. Candidates will be required to pass a test in typewriting conducted by the Commission, at a minimum speed of 30 words per minute, within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed period, they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

20. Conditions of Service for Assistants in the Central Secretariat Service, the Railway Board Secretariat Service, the Indian Foreign Service (B), the posts of Assistants in the Election Commission of India and the Department of Tourism are briefly stated in Appendix III.

K. THYAGARAJAN, Under Secy.

APPENDIX I

LIST OF UNIVERSITIES APPROVED BY THE GOVERNMENT OF INDIA

(*Vide* Rule 6)

Indian Universities

Any University incorporated by Act of the Central or State Legislature in India and other educational institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act (1956).

Universities in Burma

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

English and Welsh Universities.

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

Scottish Universities

The Universities of Aberdeen, Edinburg, Glassgow and St. Andrews.

Irish Universities

The University of Dublin (Trinity College), The National University of Dublin, The Queen's University, Belfast.

Universities in Pakistan

The University of Punjab. The Dacca University. The University of Sind, The Rajshahi University.

APPENDIX I-A

LIST OF QUALIFICATIONS RECOGNISED FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION

(*Vide* Rule 6)

1. Alankar of Gurukul Vishwa Vidyalaya, Kangri, Hardwar.
2. Shastri of Kashi Vidyapith, Banaras.
3. French Examination "Baccalaureat".
4. French Examination "Propedeutique".
5. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.
6. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.
7. Diploma in Commerce of All India Council for Technical Education.
8. Diploma in Civil, Mechanical or Electrical Engineering of the All India Council for Technical Education.

9. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.

10. 'Higher Course' of Shri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full student".

APPENDIX II

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

		Max. Marks	Time allowed
1.	Essay	100	2 hours
2.	General English . ..	200	3 hours
3.	Arithmatic	100	2 hours
4.	General Knowledge including Geographp of India ..	100	2 hours

2. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

3. Candidates are allowed the option to answer paper 1 and paper 4 either in Hindi or in English. Paper 2 and Paper 3 must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi should indicate their intention to do so in col. 7 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

4 Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects at the examination.

6. From the marks assigned to candidates in each subject such deduction will be made as the Commission may consider necessary in order to ensure that no credit is allowed for merely superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwritting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with the due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of Coins, Weights and Measures. In the question papers, wherever necessary, questions involving the use of metric system of Coins, Weights and Measures may be set.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

1. *Essay* : An essay to be written on one of the several specified subjects.

2 *General English* .

(i) Precis writing and drafting: Questions to test the understanding and power to write English. Passages will usually be set for summary of precis. Candidates will also be required to draft letter, memoranda, etc. making an intelligent use of given matter.

(ii) Questions on synonyms, antonyms, idiomatic use of words and phrases and common errors.

(iii) Parts of speech, analysis, syntax and direct and indirect speech.

NOTE.—In paper 2, questions on precis writing will carry 75 marks, drafting 75 marks and those on grammar, idioms, etc. 50 marks.

The object of papers 1 and 2 is to test the candidates' ability to write the language correctly. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language.

3. *Arithmetic* :

Ratio and proportion, percentage, average, graphical representation of data, reading of liner graphs and tabulation of data.

The questions will be designed to test intelligence, accuracy and rapidity in working.

4. *General Knowledge including Geography of India* :

Knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on Indian History of a nature which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX III

BRIEF PARTICULARS RELATING TO THE SERVICES/ POSTS TO WHICH RECRUITMENT IS BEING MADE THROUGH THIS EXAMINATION.

1 (i) *Central Secretariat Service*

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent): Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600—100—1,800.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent) : Rs. 900—50—1,250.

(3) Section Officers' Grade: Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(4) Assistants' Grade: Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in the cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.

(ii) *Railway Board Secretariat Service*

(a) The Service conditions of staff employed in the Ministry of Railways so far as recruitment training, promotion etc., are concerned, are regulated by the Railway Board's Secretariat Service Scheme, which is similar to the Central Secretariat Service Schemes.

(b) The Railway Board Secretariat Service consists of the following grades :—

(i) Assistant Director/Under Secretary : Rs. 900—50—1,250.

(ii) Section Officer: Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(iii) Assistants: Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants. Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

(c) Officers recruited direct as Assistants will be on probation for two years during which they will have to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationer from service.

(d) On the conclusion of his period of probation, the Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(e) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(f) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(g) Officers including probationers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules;

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the Rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(h) The Staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

(i) As regards leave and other conditions of service staff included in the Railway Board's Secretariat Service are treated in the same way as other Railway officers but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iii) *Indian Foreign Service (B)*

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Commerce, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) excluding Grades lower than Grade IV, are as follows :—

Grade	Designation	Scale of Pay
Grade I	Under Secretaries at Hqrs. First and Second Secretaries in Missions and Posts abroad.	Rs. 900—50—1,250.
Integrated Grades II & III	Attaches and Section Officers at Hqrs. Vice-Consuls and Registrars in Missions and Posts abroad.	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.
Grade IV	Assistants at Hqrs. and in Missions/Posts abroad.	Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

NOTE 1.—Direct Recruitment is made to the integrated Grades II and III and to Grade IV. Assistants promoted to the integrated Grades II and III are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

NOTE 2.—In accordance with the rules and orders in force from time to time, Grade I officials may be promoted to the Senior Scale of the Indian Foreign Service carrying a scale of pay of Rs. 900—50—1,000—60—1,600—50—1,800.

2. Candidates selected for Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the IFS(B) will be appointed against permanent and long-term temporary vacancies. Appointments will normally be made in the order of ranks assigned to the candidates by the Union Public Service Commission, subject to the rejection of those not found suitable for service abroad. To determine their suitability for service abroad, candidates may be required to appear for an interview before a Selection Board to be constituted by the Ministry of External Affairs, New Delhi.

3. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from Service.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Central Secretariat Service and the Railway Board Secretariat Service. Further, all such persons will be liable to service in any post either in India or abroad, to which they may be posted.

5. While employed in India, members of the Indian Foreign Service (B) are allowed such allowances in addition to their basic pay as may be admissible to other Central Government employees holding similar posts. When posted abroad, these officers are eligible for the grant of certain concessions such as foreign allowance, free furnished residential accommodation, children's education allowance, outfit allowance and passages for themselves and for their families etc., according to the scales laid down for these benefits by the Government from time to time. These concessions are liable to be withdrawn, modified or enhanced in accordance with such general decisions as the Government may take.

6. All officers appointed to the I.F.S. (B) will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, and also by other rules and Regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the I.F.S. (B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

2. *Election Commission, India*

The posts of Assistants in the Election Commission carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 like the posts of Assistants in the Central Secretariat Service. These posts are, however, not included in the Central Secretariat Service Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to posts included in the cadre of the Central Secretariat Service.

2. The persons recruited direct as Assistant will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On completion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. The next two higher grades are—

(1) Section Officers' Grade: Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(2) Under Secretaries' Grade: Rs. 900—50—1,250.

3. *Department of Tourism*

The posts of Assistants in the Department of Tourism carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 as prescribed for Grade IV of the Central Secretariat Service. These posts are, however, not included in the C.S.S. Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to the posts included in the cadre of the C.S.S.

The persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government from time to time. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in the discharge of the probationer from service.

On completion of the probation, the Government may confirm the Probationer in his appointment, or if his work or conduct has, in the opinion of the Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as the Government may consider necessary.

Assistants will be eligible for promotion to higher grade of Assistant Director (Administration) in the pay scale of Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800 in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 15th July 1966

RESOLUTION

MINERAL ORES EXPORT ADVISORY COMMITTEE

No. 15/41/63-M&F.—In further modification of Government of India Resolution No. 15/41/63-M&F, dated the 27th August 1963 as amended by Resolution of even number dated the 10th November 1964, the Government of India have decided that para 3 of the Resolution regarding constitution of this Committee may be deleted and the following substituted instead :—

3. *Constitution*

The Committee will comprise some officials of Government, the M.M.T.C. of India, the N.M.D.C. of India and some representatives of mining and the export trade. The Committee may co-opt more members whenever necessary. The constitution of the Committee will be as under :—

Chairman

1. Shri G. L. Bansal,
Secretary General,
Federation of Indian Chambers of
Commerce and Industry, New Delhi.

Members

2. Joint Secretary,
Ministry of Commerce, New Delhi.
3. Chairman, Minerals & Metals Trading
Corporation, New Delhi.
4. Joint Secretary,
Ministry of Mines & Metals, New Delhi.
5. Director, Indian Bureau of Mines,
Ministry of Mines & Metals, New Delhi.
6. Director (Traffic and Transportation),
Ministry of Railways (Railway Board),
New Delhi.
7. A representative of Ministry of Transport,
(Road Wing), New Delhi.

8. A representative of Ministry of Transport, (Port Wing), New Delhi.

9. A representative of the National Mineral Development Corporation of India Ltd., New Delhi.

10. A representative of the Bharat Chamber of Commerce, Calcutta.

11. A representative of the Indian Union Minerals Association, Calcutta.

12. A representative of the Utkal Mining & Industrial Association, Calcutta.

13. A representative of the Eastern Zone Mining Association, Chaibasa.

14. A representative of the South Indian Minerals Association, Madras.

15. A representative of the Mysore State Minerals Producers' Coop. Union Ltd., Bangalore.

16. A representative of the Western Indian Mineral Association, Bombay.

17. A representative of the Bombay Region Mineowners Association, Londa.

18. A representative of the Mineral Industry Association, Nagpur.

19. A representative of the Rajasthan Iron Ore Mineowners and Exporters Association, Jaipur.

20. A representative of the Mica Export Promotion Council, Calcutta.

21. Shri R. N. Deshmukh, Morsi Road, Amravati, Maharashtra.

22. A representative of the Goa Mineral Ore Exporters' Association, Panjim, Goa.

23. A representative of the Goa Mineowners Association, Panjim, Goa.

24. A representative of the Federation of Indian Mineral Industries, New Delhi.

Member-Secretary

25. Shri C. V. Rama Rao, General Manager (Ores), Minerals & Metals Trading Corporation, New Delhi.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

K. N. WAHAL, Under Secy.

New Delhi, the 20th July 1966

No. 12/1/66-*C.Ptv.*—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 135 B of the Defence of India (Seventh Amendment) Rules 1965, the Central Government hereby appoints the following officers as Assistant Custodians of Migrant Property in addition of their duties :—

1. Shri Khushi Ram, Tehsildar, Anupgarh Tehsil, Ganganagar District, Rajasthan.

2. Shri Suraj Karan, Tehsildar, Bikaner Tehsil, Bikaner District, Rajasthan.

3. Shri Mathuradass Bissa, Tehsildar, Kolayat Tehsil, Bikaner District, Rajasthan.

4. Shri Chatur Beharilal Gupta, R.A.S., Additional Collector, Barmer and Jaisalmer Tehsils and Districts, Rajasthan.

S. BANERJEE, Dy. Secy.

MINISTRY OF MINES AND METALS

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd July 1966

No. 20/11/66-*MIII.*—In pursuance of the recommendations of the Mineral Policy Conference held in 1947, the Indian Bureau of Mines was set up in March 1948, to function primarily as an advisory body. With the enactment of the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act by the Central Government in September 1948, and the notification of the Mineral Concession Rules 1949, the Bureau's sphere of work increased considerably. Apart from its purely advisory capacity, it became necessary for the Bureau to function as a field and research organisation and also to attend to the conservation of the country's mineral resources and their utilisation in the best possible manner. The functions of the Bureau, thus constituted under the Government of India's Resolution No. MII-150(125) dated 9-8-1950, were as follows :—

(i) Advising the Central and State Governments on all matters relating to the grant of mineral concession and also on the exploration, exploitation and utilisation of the country's mineral resources.

(ii) Periodic inspection of mines, for effecting the systematic development of mineral deposits, the elimination of avoidable waste and the promotion of improved methods of mining.

(iii) Conducting drilling and other prospecting operations to prove and estimate the workable reserves in mineral deposits in areas indicated by the Central Government as areas in which operations preliminary to the opening of mines may be conducted and to conduct test mining independently or in conjunction with other governments or private organisations in such areas.

(iv) Conducting research on the beneficiation of low grade ores and the industrial utilisation of minerals and mineral products, as well as on mining problems, in collaboration with other research organisations.

(v) Conducting analyses of ores and minerals in connection with the work of the Bureau, and also for the public as far as time and circumstances permit.

(vi) Collection and publication of statistics relating to mineral production in India, mineral stocks, exports, local consumption, etc.; and collection and maintenance of information regarding world mineral production, world mineral trade, foreign mining rules and other related matters.

(vii) Publication of Bulletins and monographs of investigations relating to mining and the mineral industry.

(viii) Assisting the mineral trade in the marketing of minerals.

(ix) Undertaking any other function entrusted to the Bureau by the Central Government from time to time.

On the other hand, the Geological Survey of India, which was set up by the Government of India in 1851, is responsible for geological mapping and exploratory drilling calculated to delineate mineralised zones in the country. In course of time some overlapping between these two organisations had crept in and to eliminate avoidable duplication, the prospecting, drilling and mining divisions of the Indian Bureau of Mines have been merged with the Geological Survey of India with effect from 1-1-1966. As a result of this reorganisation, the Indian Bureau of Mines is now discharging all the functions enumerated above with the exception of (iii).

2. For carrying out these residuary functions, the Indian Bureau of Mines is organised into 3 main divisions :

(i) Mineral Economics Division.

(ii) Ore Dressing and Pilot Plant Laboratories.

(iii) Mines Control and Conservation of Minerals Division.

3. There has been a feeling that the present set-up of Indian Bureau of Mines is not adequate for achieving the objectives of conservation of minerals and the development of mineral wealth of the country consistent with the increasing requirements of industry and export trade. The mining industry is in need of technical assistance and consultancy for scientific development of mines and installation of modern mining equipment and introduction of modern mining techniques and practices. The existence of sizable deposits of low grade ores has also posed important problems of beneficiation and economic utilisation.

4. It has, accordingly, been decided to set up a Committee to review the present organisation of the Indian Bureau of Mines and its functions in the context of these requirements and the need for providing requisite assistance to mining industry, both in the private and public sectors, to step up production and reduce mining costs.

5. The terms of the reference of the Committee will be as under :—

(i) To make an appraisal of the work done by the various Divisions of the Indian Bureau of Mines with reference to the above functions, (excluding prospecting and drilling) as listed in para 1 above.

(ii) To examine whether these functions are appropriate in the context of the emerging requirements of mining industry and the economy of the country and to suggest modifications or additions to these functions, as may be considered desirable.

(iii) To review the organisational structure of the Indian Bureau of Mines and suggest suitable lines of reorganisation with a view to fulfilling the objectives and functions of the organisation.

(iv) To review the working of the Mineral (Conservation and Development) Rules 1958 and to examine utility and necessity of the salient provisions with reference to the basic objectives of the legislation, e.g., Conservation of mineral wealth of the country.

(v) To examine how far regulatory functions of the Indian Bureau of Mines, as envisaged in the Mineral (Conservation and Development) Rules, 1958, have been effective in furthering the interests of mining industry and to advise whether the continuance of these regulatory functions in the present or a modified form is really necessary.

(vi) To suggest how the Indian Bureau of Mines can be reorganised, equipped and strengthened to provide systematic guidance, advice and consultancy to the mining industry, and in particular the following services :—

(a) appraisal of mineral deposits;

(b) design of mines, including selection of mining techniques;

(c) beneficiation, ore dressing, concentration and extraction of metals;

(d) design and selection of suitable mining equipment and the preparation of flow-sheets and diagrams.

(vii) To examine and identify the areas of duplication and overlapping between the Indian Bureau of Mines and the other departments of Government of India, e.g. Geological Survey of India, Inspectorate of Mines, National Laboratories, etc.

6. The composition of the Committee will be as follows :—

Chairman

1. Shri B. C. Mukharji.

Members

2. Shri A. B. Guha,
Adviser (Resources), Planning Commission,
New Delhi.

3. Shri S. V. Subrahmanyam,
General Manager,
Jaduguda Mines Project, Jaduguda.

4. Shri B. H. Engineer,
Divisional Manager (Raw Materials),
Tata Iron & Steel Company,
Jamshedpur.

Secretary

5. Shri A. M. Hussain,
Dy. Mineral Economist,
Indian Bureau of Mines, New Delhi.

The Committee may co-opt any other technical expert in course of its deliberations.

7. The Committee will submit its report within 3 months.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Committee.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. N. VASUDEVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Family Planning)

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd July 1966

No. 14-1/66-*C&C*(*F.P.*).—The Government of India is pleased to appoint Dr. K. C. Patnaik, Director, Central Bureau of Health Intelligence in the Directorate General of Health Services as a Member of the Demographic Advisory Committee as reconstituted in the Ministry of Health Resolution No. F.12-53/65-FP.II dated the 27th January, 1966.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th July 1966

No. 26(5)/66-*Tech.I.*—The Government of India have been considering the question of establishing a Research-*cum*-Training Centre in Rice Technology where research and training in modern methods of handling, drying and storage and processing of paddy from harvesting till marketing would be imparted. They have now decided to appoint a Committee to prepare a survey report for the establishment of a centre in India and submit its recommendations to Government on this subject. The Committee will consist the following members :—

Chairman

1. Shri K. T. Chandy.

Members

2 Dr. K Ramaiah,
Vice Chancellor, Agricultural University,
Bhuvaneswar.

3. Shri M. N. Suri,
Director, Central Mechnical Engg. Research Institute,
Durgapur.

Member-Secretary

4. Dr. S. V. Pingale,
Director (S. & I), Deptt. of Food.

The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To suggest a suitable location for the proposed centre;

(ii) To indicate broadly the lines of research to be undertaken at the Centre;

(iii) To indicate the nature of the courses of training to be started in the Training Centre with the following details :—

(a) Subjects of study,

(b) Whether Certificate, diploma or Degree should be given after the training.

(c) The duration of the training courses,

(d) Whether any affiliation should be sought to an existing University or Institution,

(e) The minimum essential qualifications to be prescribed for admission to the Institute,

(f) The number of students to be admitted each year, and

(g) Organisation and all other ancillary matters relating to the work of the Centre in the field of Rice Technology, processing, handling and agricultural engineering.

(iv) To indicate the staffing and organisational pattern of the proposed Centre and to make an assessment of the laboratory and workshop facilities to be provided at the Centre, and

(v) To make an assessment of the recurring and non-recurring expenditure of the training centre and to make suitable recommendations regarding the grant if any, to be given by the Government of India for this purpose.

In order to study the various problems falling within the scope of the enquiry the Committee may visit any State and hold its meetings at any place in the country as it may consider necessary.

The Committee will submit its report to Government within a period of four months.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be sent to all the State Governments and Administrations.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. L. DIAS, Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

RESOLUTION

New Delhi, the 19th July 1966

SUBJECT :—*All India Council for Technical Education—Amendment to the Resolution of the—*

No. F. 1-2/64-*T*-2.—In partial modification of the Government of India in the late Department of Education Resolution No. F. 16-10/44-E.III, dated the 30th November 1945, as amended from time to time (up to 29th October 1964), the President is pleased to order that the following clauses may be added/amendments made in the Resolution establishing the All India Council for Technical Education :—

(i) Sub-clause (a) of clause (i) of paragraph 3 may be amended to read as follows :—

"(a) Chairman—Minister-in-charge, Central Government. (On occasions when he is unable to preside over a meeting of the Council, the members present should elect a Chairman from amongst themselves for the particular meeting)."

(ii) The word 'Joint' may be deleted from Sub-clause b(ii) of clause (i) of paragraph 3 and paragraph 5.

(iii) The following sub-clause may be added after sub-clause (s) of clause (i) of paragraph 3 :—

"(t) Director General, Council of Scientific & Industrial Research (*Ex-officio*)."

ORDER

2. ORDERED that the Resolution may be published in the Gazette of India.

3. ORDERED also that copies may be communicated to all the State Governments including Union Territories and Ministries of Government of India.

A. B. CHANDIRAMANI, Jt. Educational Adviser

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, the 20th July 1966

F. No. 16/6/65-*SCT.II*—The Government of India have appointed Shri Chandra Manilal Chowdhary, M.P., Shri Chuni Lal, M.P. and Shri Jagannath Pahadia, M.P., as members of the Central Advisory Board for Harijan Welfare in the vacancies caused by the appointment of Shri Rameshwar Sahu, M.P. as a Union Minister and Shri Amrit Lal Yadav, MLA and Shri Chand Ram MLA as Minister in the States of Rajasthan and Punjab respectively.

ORDER

ORDERED that the above be published in the Gazette of India.

S. C. SEN GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND AVIATION

(Department of Transport, Shipping and Tourism)

(Transport Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 19th July 1966

No. 55-*MA*(9)/65.—The Central Government is pleased to make the following amendments in the Ministry of Transport and Aviation, Department of Transport, Shipping and Tourism, Resolution No. 55-MA(9)/65, dated the 25th May, 1966, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, namely :—

1. Against item 7, under the heading "A. DECK PASSENGER WELFARE COMMITTEE, BOMBAY", *for* the words 'The Principal Port Officer and Engineer, State Government of Maharashtra, Bombay" *read* "The Chief Ports Officer and Deputy Secretary to the Government of Maharashtra, Buildings and Communications Department, Bombay".

2. Against item 4, under the heading "C. DECK PASSENGER WELFARE COMMITTEE, MADRAS" *for* the words "The Senior Traffic Manager (Operation), Madras Port Trust Madras" *read* "The Deputy Traffic Manager I, Madras Port Trust, Madras" and against item 11 thereof, *for* "Shri P. Maruthi Pillai" *read* "Shri P. Maruthai Pillai".

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat (10 copies including 5 for Committee Branch), the Planning Commission, All Ministries of the Government of India, All State Governments, the Chairman, Calcutta Port Commissioners, Calcutta, the Chairman, Bombay Port Trust, Bombay, the Chairman, Madras Port Trust, Madras, The Indian National Steamship Owners Association, Scindia House, Ballard Estate, Fort, Bombay, the Director General of Shipping, Commerce House, Ballard Estate, Fort, Bombay (with 100 spare copies) for distribution to the Shipping Companies in India, the members of the National Harbour Board and National Shipping Board, and the Chairman and Members of the Deck Passenger Welfare Committees, Bombay, Calcutta, and Madras.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NAGENDRA SINGH, Secy.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th July 1966

No. 28-*MT*(1)/65.—For the word 'May' appearing in line 4 of the Ministry of Transport and Aviation, Department of Transport, Shipping and Tourism Resolution No. 28-MT(1)/65, dated the 21st June 1966, the word 'July' shall be *substituted*.

P. K. RAKSHIT, Under Secy.

L152GI/66

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

RESOLUTION

New Delhi, the 16th July 1966

No. WB-21(36)/65.—The recommendations of the Central Wage Board for Port & Dock Workers at major ports for grant of interim relief were published as appendix to Government Resolution No. WB-21(13)/65, dated the 27th April 1965. After considering certain representations made to it, the Wage Board has recommended that the following may be substituted in place of sub-clause (5) of clause (E) in Para I of the Appendix to the aforesaid Resolution :—

"Persons mainly employed in a Dock as defined in para 2(3) of the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961 made by the Central Government in exercise of powers conferred by Section 4(1) of Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948."

2. Government have decided to accept the recommendations of the Wage Board and to request the concerned employers to implement the recommendations in the light of the above modification as early as possible.

ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 22nd July 1966

No. 2/75/65-*I&E*.—From September 1964 there have been several complaints by trade unions to the Government alleging forced retirement and retrenchment of employees by certain Petroleum Oil Companies in contravention of the legal provisions on the subject. The matter also came up before the Lok Sabha on the 22nd March 1965 in the form of a starred question to which the Minister for Labour and Employment replied promising to look into the facts. At a Tripartite Meeting convened by the Minister for Labour and Employment and the Minister for Petroleum and Chemicals in October 1965, the Oil Companies denied that there was any forced retirement or retrenchment. They explained that what was complained of was a purely voluntary retirement scheme based on individual applications voluntarily made by workers who chose to avail themselves of certain favourable terms of premature retirement offered by the employers. In view of the divergence of views expressed at the meeting, a Tripartite Committee was appointed under the chairmanship of Shri R. L. Mehta (then Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment) to look into the whole problem and submit a report by 31st December 1965. The terms of reference of the Committee were—

"The Tripartite Committee would look into the whole problem of job security and reduction of staff....The investigation would include an examination of the nature and extent of introduction of machines and automatic devices and their effect on efficiency and other relevant matters."

The Committee included two representatives of trade unions (INTUC—National Federation of Petroleum Workers and AITUC—All India Petroleum Workers' Federation), two representatives of employers (Burma Shell and Caltex) and an officer of the Ministry of Petroleum and Chemicals in addition to the Chairman.

2. The Committee submitted its report on the 21st April 1966. The main report has been signed by the two official members and two trade union representatives; the two Oil Companies' representatives do not agree with the conclusions and recommendations of the majority and have set out their views in a Minute of dissent.

3. The main findings and recommendations of the Committee are the following :—

(i) The Companies, in spite of opportunity given to them by the Committee, have not produced material which establishes the surplus of staff; they have merely claimed in general way that their estimates of surpluses are based on systematic method studies carried out by their own officers over a period of years with a view to simplification of procedures and elimination of waste.

(ii) The Committee recommends that in retrenching surplus staff if any, the procedure laid down in the Industrial Disputes Act should be followed.

(iii) The Committee has no objection to the continuance of an early voluntary retirement scheme, if the Companies will agree to the Committee's recommendation that all the individual applications are

considered and decided jointly by representatives of employees and employers This will ensure that persons genuinely wanting to retire early are not prevented from doing so and nobody is coerced to retire.

4 The Government commend the recommendations in para 3 above to the employers and trade unions concerned for their guidance in resolving, through bilateral negotiations, their disagreements on this question.

5 Government also thank the Chairman and Members of the Committee for their services in connection with the work of the Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. C MATHEW, Secy

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1966